Five Year Plan since the same has not been finalised yet. In the Demand for Grants 1992-93 a provision of Rs. 3 lakhs has been provided for the first phase of Udaipur Bypass costing about Rs. 3 crores.

Private Nursing Homes in Delhi

*51. SHRI ASHWANI KUMAR :
SHRI JAGDISH PRASAD MATHUR :

Will the Minister of HEALTH AND FAMILY WELFARE be pleased to state :

(a) what are the rules and guidelines laid down by Government for registration of private nursing homes in Delhi ;

(b) whether 'No Objection Certificate' from the D.D.A. is essential ;

(c) the rate of levy charged by the D.D.A. from nursing homes above the current rate of land as commercial conversion charges ; and

(d) the number of nursing homes in the Capital and the number of those duly registered with the Delhi Administration.

THE MINISTER OF HEALTH AND FAMILY WELFARE (SHRI M. L. FOTEDAR) : (a) to (d) Private Nursing Homes in Delhi are required to be registered under the Delhi Nursing Homes Registration Act, 1953 and the rules framed thereunder. To be eligible for such registration, a Nursing Home should satisfy the conditions and specifications relating to location; building; space accommodation for patients; water supply, labour room and operation theatre; arrangements for isolating infection cases; equipment and linen; medicines; food and qualified manpower etc., as laid down in the Delhi Nursing Homes Registration Rules, 1963.

No Objection Certificate from Delhi Development Authority is required to the effect that the nursing home conforms to the approved land use. Rates of levy as commercial conversion charge have not been finalised so far.

As per information furnished by Delhi Administration, there are 445 private Nursing Homes in Delhi, out of which 129 are registered.

मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्गों का सुधार

*52. **श्री राधाकिशन मालवीय** : क्या **जल-भूतल परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने मध्य प्रदेश से होकर गुजरने वाले राष्ट्रीय राजमार्गों का सुधार तथा आधुनिकीकरण करने के लिए कोई योजनाएं तैयार की हैं, और

(ख) यदि हां, तो उनका ब्यौरा क्या है ?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्यमंत्री (श्री जगदीश टाइटलर) (क) और (ख) राष्ट्रीय राजमार्गों का आधुनिकीकरण एक सतत प्रक्रिया है । मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्ग प्रणाली में सुधार हेतु दो करोड़ रु० से अधिक लागत की स्कीमों, जिन पर पहले से ही काम चल रहा है, के ब्यौरे नीचे दिए गए हैं :—

क्रम सं०	नाम	अनुमानित लागत
1	रा० रा० 12 के 324 से 340 कि० मी० तक के मौजूदा 2 लेन वाले पेवमेंट को सुदृढ़ करना	2.11 करोड़ रु०
2	रा० रा० 7 के 544-556 कि० मी० और 558 से 570 कि० मी० तक के खंड को सुदृढ़ करना और पुलिया का पुनर्निर्माण ।	2.75 करोड़ रु०
3	रा० रा० 12 के (i) 67/4-94 कि० मी० (ii) 130-148 कि० मी० खंड को सुदृढ़ किए बगैर चौड़ा करना ।	4.26 करोड़ रु०
4	रा० रा० 12 के 108 से 130/2 कि० मी० खंड को सुदृढ़ किए बगैर चौड़ा करना	2.30 करोड़ रु०
5	रा० रा० 12 के 18 से 58 कि० मी० खंड को सुदृढ़ किए बगैर चौड़ा करना	2.95 करोड़ रु०
6	रा० रा० 7 पर नर्मदा नदी पर तलवाड़ा घाट पर उच्च तलीय जलसेतु और सड़क पुल	2.46 करोड़ रु०
7	रा० रा० 7 के 88.6 कि० मी० से 110 कि०मी० खंड को सुदृढ़ करना	2.31 करोड़ रु०